ASSOCHAM IN THE NEWS

HINDU BUSINESS LINE

Dated : 29-12-2017

Credit growth likely to be muted at 8% this fiscal, says Assocham

Will be driven mainly by retail and farm loans

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, December 28

A slowdown in the economy coupled with high stress levels in the banking sector is expected to restrict credit growth at around 8 per cent during the current fiscal despite government's thrust on loan expansion, says a study by industry chamber Assocham.

However, this would be slightly better than the five-decade low growth of 5.1 per cent in non-food credit recorded in the financial year ended March 2017.

Growth in credit this year would be mainly driven by retail and farm loans, it said, adding expansion could also come from some segments of the industry related to infrastructure, if they pick up in the second half of the current fiscal.

Recapitalisation would have limited impact on credit growth and that too would be restricted to the last quarter of the ongoing financial year, Assocham said

There could be some uptick in lending towards the micro, small and medium enterprises (MSME) sector with the government asking banks to increase their exposure to the sector as they are one of the largest employers, it said.

Capital infusion

One of the objectives of the ₹2.11-lakh crore capital infusion programme announced by the government in October is to enable banks to enhance lending to industry, especially MSMEs by strengthening balance sheets of NPA-ridden public sector banks (PSBs), it said.

Non-performing assets (NPAs) of public sector banks increased to ₹7.33 lakh crore as of June 2017, from ₹2.78 lakh crore in March 2015.

Notably, the corporate sector is not getting loans from banks as lenders have become risk averse due to mounting NPAs.

To make matters worse, companies with good ratings are tapping the bond market as rates are cheaper there. The only segments that are witnessing healthy growth are personal and agriculture credit with a jump of over 10 per cent, it said. "This situation will continue more or less unchanged for the rest of the financial year, limiting credit growth to between 8 and 9 per cent for the fiscal, even after taking into account acceleration during the second half of the fiscal, referred to as busy credit season, and proposed strengthening of balance sheets of PSBs," it said.

Recapitalisation would have limited impact on credit growth and that too would be restricted to the last quarter of the ongoing fiscal, it said.

The Financial Express

Dated : 29-12-2017

'Credit growth likely to be muted at 8%'

A SLOWDOWN IN the economy coupled with high stress level in the banking sector is expected to restrict credit growth at around 8% during the current fiscal despite government's thrust on loan expansion, says a study by industry chamber Assocham. However, this would be slightly better than the five decade low growth of 5.1% in non-food credit recorded for the financial year ended March 2017. Growth in the credit this year would be mainly driven by the retail segment and farm loan, it said, adding expansion could also be contributed by some segments of the industry related to infrastructure if they pick up in the second half of the current fiscal.

The Statesman

Dated : 29-12-2017

'Credit growth likely to be muted at 8%'

NEW DELHI, 28 DECEMBER

A slowdown in the economy coupled with high stress level in the banking sector is expected to restrict credit growth at around 8 per cent during the current fiscal despite the government's thrust on loan expansion, says a study by industry chamber Assocham.

However, this would be slightly better than the five decade low growth of 5.1 per cent in non-food credit recorded for the financial year ended March 2017. Growth in the credit this year would be mainly driven by the retail segment and farm loan, the business chamber said. PTI

ASSOCHAM IN THE NEWS

Dainik Jagran **Dated : 29-12-2017**

बैंक कर्ज की रफ्तार धीमी बनी रहने की आशंका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था की सुस्ती और बैंकों में बढ़ते एनपीए ने बैंकों की कर्ज की रफ्तार को धीमा कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में इन वजहों से बैंक कर्ज की वृद्धि दर 8 फीसद तक सीमित रह सकती है। जबकि सरकार लगातार उद्योगों को बैंक कर्ज के विस्तार के उपाय कर रही है।

अध्ययन

- चालू वित वर्ष में बैंकों के कर्जों की वृद्धि दर आठ फ़ीसद : एसोचैम
- अर्थव्यवस्था की सुस्ती ने धीमी की बैंक कर्ज की रफ्तार

उद्योग संगठन एसोचैम के एक अध्ययन के मुताबिक भले ही इस साल भी बैंक कर्ज की रफ्तार सीमित रहेगी। लेकिन यह बीते वित्त वर्ष के गैर खाद्य ऋणों की 5.1 फीसद की रफ्तार से अधिक होगी। बीता साल बैंक कर्ज की रफ्तार के लिहाज से पांच दशक में सबसे सुस्त वर्ष रहा था। अध्ययन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में बैंक कर्जों में जो भी वृद्धि रही है, वह रिटेल और कृषि क्षेत्र से आई है। अगर वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कुछ सुधार हुआ तो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बैंक कर्ज में मामूली मांग आ सकती है। सरकार लगातार सूक्ष्म, लघु और मझोली इकाइयों (एमएसएमई) को बैंकों से मिलने वाले कर्ज में वृद्धि पर जोर दे रही है। चूंकि यह क्षेत्र रोजगार के सबसे अधिक अवसर उपलब्ध कराता है इसलिए सरकार का मानना है कि बैंकों को इस क्षेत्र की इकाइयों को कर्ज की रफ्तार बढ़ानी चाहिए। इसलिए बैंक कर्ज की वृद्धि दर में इस क्षेत्र का योगदान भी अहम रहेगा। सरकार ने इसी साल अक्टूबर में बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के कार्यक्रम की घोषणा की थी। ताकि एनपीए के चलते खराब हो रही बैंकों की बैलेंस शीट को दुरुस्त किया जा सके। पूंजी पर्याप्तता के लिहाज से मजबूत होकर बैंक एमएसएमई क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सकें। सरकारी बैंकों का एनपीए मार्च 2015 में 2.78 लाख करोड़ रुपये के थे जो जून 2017 में बढ़कर 7.33 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

एसोचैम के मुताबिक गंभीर बात यह है कि कॉरपोरेट सेक्टर को बैंकों से कर्ज नहीं मिल रहा है। बढ़ते एनपीए के चलते बैंक सतर्कता बरत रहे हैं। दूसरी वजह यह भी है कि बांड मार्केट में ब्याज दर कम होने से अच्छी रेटिंग प्राप्त कंपनियां वहां से पूंजी जुटा रही हैं। केवल व्यक्तिगत और कृषि कर्जों में ही दस फीसद की वृद्धि दर देखने को मिली है। यह स्थिति बाकी बचे वित्त वर्ष में भी बने रहने की संभावना है। अध्ययन मानता है कि बैंकों के पूंजीकरण से स्थिति में बहुत अधिक बदलाव होने की आशा नहीं है। लेकिन अगले वित्त वर्ष में इसका प्रभाव देखा जा सकता है।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Hindustan (Hindi)

Dated : 29/12/201

मौजूदा वित्त वर्ष में ऋण वृद्धि 8% रहेगी : एसोचैम

अर्थव्यवस्था में नरमी और बैंकिंग क्षेत्र में संकटग्रस्त संपत्तियों के अत्यधिक दबाव के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में ऋण वृद्धि करीब आठ प्रतिशत रह सकती है। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम ने यह अनुमान व्यक्त किया है। एसोचैम ने कहा, इस साल ऋण वृद्धि में मुख्यतौर पर खुदरा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का बेहतर योगदान रहा है। उत्तरार्द्ध में आधारभूत संरचना से जुड़े क्षेत्र भी ऋण वृद्धि में योगदान दे सकते हैं।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Viraat Vaibhav **Dated : 29/12/2017**

मौजूदा वित्त वर्ष में आठ प्रतिशत रहेगी ऋण वृद्धि : एसोचैम

एजेंसी ■ नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था में नरमी तथा बैंकिंग क्षेत्र में संकटग्रस्त संपत्तियों के अत्यधिक दबाव के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में ऋण वृद्धि करीब आठ प्रतिशत रह सकती है। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम ने यह अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि, यह मार्च 2017 में समाप्त हुए वित्त वर्ष में इसके 5.1 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में यह दर पांच दशक के निचले स्तर पर थी। एसोचैम ने जारी बयान में कहा कि इस साल ऋण में वृद्धि की मुख्यतौर पर खुदरा क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र का बेहतर योगदार रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष के उत्तरार्द्ध में यदि तेजी आई तो आधारभूत संरचना से जुड़े कुछ क्षेत्र भी ऋण वृद्धि में योगदान दे सकते हैं। सरकार द्वारा बैंकों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपक्रमों को अधिक ऋण प्रदान करने के लिए कहे जाने से रिण वृद्धि में इनका भी योगदान संभव है। सरकार ने बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपए की नई पूंजी डालने का जो कार्यक्रम बनाया है उसका एक मकसद बैंकों की कर्ज देने की क्षमता को बढ़ाना भी है। पूंजी आधार मजबूत होने से बैंक उद्योगों और विशेष तौर से एमएसएमई को अधिक कर्ज दे सकेंगे। बैंकों की फंसी कर्ज राशि (एनपीए) अधिक होने की वजह से वह ज्यादा कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) मार्च 2015 के 2.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर जून 2017 में 7.33 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यही वजह है कि बैंक अब कर्ज देने में काफी सोच विचार कर रहे हैं और उद्योगों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पा रहा है। बेहतर रेटिंग वाली कंपनियां बाजार से पूंजी जुटा रही हैं।

ASSOCHAM IN THE NEWS

Veer Arjun **Dated : 29/12/2017**

मौजूदा वित्त वर्ष में आठ प्रतिशत रहेगी ऋण वृद्धि : एसोचैम

नई दिल्ली, (भाषा)। अर्थव्यवस्था में नरमी तथा बैंकिंग क्षेत्र में संकटग्रस्त संपत्तियों के अत्यधिक दबाव के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में ठुण वृद्धि करीब आठ प्रतिशत रह सकती है। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम ने यह अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि, यह मार्च 2017 में समाप्त हुए वित्त वर्ष में इसके 5.1 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में यह दर पांच दशक के निचले स्तर पर थी। एसोचैम ने जारी बयान में कहा कि इस साल ठुण में वृद्धि की मुख्यतौर पर खुदरा क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र का बेहतर योगदार रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष के उत्तरार्द्ध में यदि तेजी आयी तो आधारभूत संरचना से जुड़े कुछ क्षेत्र भी ठुण वृद्धि में योगदान दे सकते है। सरकार द्वारा बैंकों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपक्रमों को अधिक ठुण प्रदान करने के लिए कहे जाने से रिण वृद्धि में इनका भी योगदान संभव है। सरकार ने बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये की नई पूंजी डालने का जो कार्यक्रम बनाया है उसका एक मकसद बैंकों की कर्ज देने की क्षमता को बढ़ाना भी है। पूंजी आधार मजबूत होने से बैंक उद्योगों और विशेषतौर से एमएसएमई को अधिक कर्ज दे सकेंगे। बैंकों की फंसी कर्ज राशि (एनपीए) अधिक होने की वजह से वह ज्यादा कर्ज नहीं दे पा रहे है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) मार्च 2015 के 2.78 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2017 में 7.33 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।